



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2009/फाल्गुन 5, 1930

No. 25]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2009/PHALGUNA 5, 1930

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

## अधिसूचना

मुम्बई, 18 फरवरी, 2009

सं. टीएमपी/36/2005-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, चेन्नई पत्तन न्यास में मौजूदा दरमान की वैधता 31 दिसम्बर, 2008 के बाद से बढ़ाता है।

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/36/2005-सीएचपीटी

चेन्नई पत्तन न्यास

—आवेदक

## आदेश

(फरवरी, 2009 के 12वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) के दरमान की वैधता को 31 दिसम्बर, 2008 तक बढ़ाते हुए 30 सितम्बर, 2008 को एक आदेश पारित किया था।

2. सीएचपीटी ने अपने पत्रों दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 2 जनवरी, 2009 और 9 जनवरी, 2009 द्वारा मौजूदा दरमान की वैधता को 31 दिसम्बर, 2008 से आगे के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है।

3. सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 18 सितम्बर 2008 और 9 जनवरी, 2009 द्वारा अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल किया है। इस प्रस्ताव पर प्रासंगिक उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। सामान्य परामर्शी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए इस प्राधिकरण द्वारा मामले पर कार्यवाही करने और इस मामले पर इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम विचार किए जाने में कुछ समय लगेगा। अतः सीएचपीटी में मौजूदा दरमान की वैधता को 31 दिसम्बर, 2008 से आगे के लिए बढ़ाना जरूरी है।

4. अतः इस प्राधिकरण ने सीएचपीटी में मौजूदा दरमान की वैधता को 30 जून, 2009 तक अथवा अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए सीएचपीटी के प्रस्ताव पर पारित किए जाने वाले आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने का निर्णय लिया है। तथापि, मौजूदा दरमान का वैधता विस्तार इस शर्त के अधीन है कि 1 अप्रैल, 2008 के बाद की अवधि के लिए स्वीकार्य लागत और सीएचपीटी को प्रोद्भूत होने वाले स्वीकार्य प्रतिलाभ से ऊपर का अधिशेष अगले चक्र के लिए निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा, जैसाकि आदेशों दिनांक 14 जुलाई, 2008 और 30 सितम्बर, 2008 में पहले ही विनिर्दिष्ट किया गया है।

ब्रह्म दत्त, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/143/08-असा.]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 18th February, 2009

No. TAMP/36/2005-CHPT.— In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates at Chennai Port Trust beyond 31 December, 2008, as in the Order appended thereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/36/2005-CHPT

Chennai Port Trust

—Applicant

## ORDER

(Passed on this 12th day of February, 2009)

This Authority had passed an Order on 30 September, 2008, extending the validity of the Scale of Rates of Chennai Port Trust (CHPT) till 31 December, 2008.

2. The CHPT *vide* its letters dated 16 December, 2008, 2 January, 2009 and 9 January, 2009 has, *inter alia*, requested to extend the validity of the existing Scale of Rates beyond 31 December, 2008.

3. The CHPT *vide* its letters dated 18 September, 2008 and 9 January, 2009 has filed a proposal for general revision of its Scale of Rates. The proposal has been taken on consultation with the relevant users/user organizations. It will take some time for processing the case by this Authority following the usual consultation process and for the case to mature for final consideration of this Authority. It is, therefore, necessary to extend the validity of the existing Scale of Rates at CHPT beyond 31 December, 2008.

4. The Authority, therefore, decides to extend the validity of the existing Scale of Rates at CHPT till 30 June, 2009 or till the effective date of implementation of the Order to be passed on the proposal of CHPT for general revision of its Scale of Rates, whichever is earlier. However, the extension of validity of the existing Scale of Rates is subject to the condition that the surplus over and above the admissible cost and permissible return accruing to CHPT for the period after 1 April, 2008 will be set off fully in the tariff to be fixed for the next cycle, as has already been stipulated in the Orders dated 14 July, 2008 and 30 September, 2008.

BRAHMDUTT, Chairman

[ADVT III/4/143/08-Exty.]